Frustration among the people of Jammu

1023. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the growing frustration and discontentment among the people of Jammu;

(b) what remedial steps Government propose to take in this regard;

(c) whether it is a fact that Government had appointed a number of commissions in this reard; and

(d) if so, the recommendations made by these commissions together with details of those accepted and implemented and also those not acceptable together with the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (d) The Government of Jammu and Kashmir has advised that this issue of regional inequalities had often been the subject of public debate and from time to time committees and commissions had been appointed to enquire into those issues and to make recommendaions which would contribute to greater regional equity. A Commission was appointed in June, 1979 under the Chairmanship of Shri Justice S. M. Sikri, retiored Chief Justise of India. In 1983, another commission headed by Shri Justice J. N. Wazir, retired Chief Justice of High Court of Jammu and Kashmir reported on rationalisation of administrative units. The numerous recommendations made by the Commissions have been considered by the State Government and follow up action taken from time to time.

Terrorist activities in Delhi

1024. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports that terrorists have sneaked into Delhi during the last few months and consequently several incidents of bomb blasts in buses markets and crowded places have been their handiwork;

(b) if so, whether Delhi police has been geared up and given any special training to meet the situation; and

(c) the number of hide-outs of terrorists raided and the number of terrorists rounded up in Delhi during the last six months?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) Yes, Sir. There is informatoin that some terrorists have sneaked into the Capital during the last few months.

(b) Anti-Terrorist Cells have been established in each Police District. Bomb Disposal Squads have also been formed and young trained officers are being posted in these squads.

(c) 629 hide-outs of terrorists were raided during the period from 16th August, 1991 to 15th February, 1992 and 24 terrorists arrested.

नक्सली समस्या से निबटने के लिए समन्वित कदम

1025. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1991 में सरकार ने नक्सली कार्यकलापों से प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई थी ;

(ख) उस बैठक में क्या यह निर्णय लिया गया था कि नक्सली समस्या से निपटने के लिए सभी राज्यों द्वारा समन्वित कदम उठाए जाएं ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को नक्सली समस्या से निपटने के लिए

केन्द्रीय बल उपलब्ध कराए गए हैं तथा वहां इन बलों की कितनी कम्पनियां तैनात की गई हैं ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में केन्द्रीय बलों की अब तक कितनी कम्पनियां भेजी हैं ; और

(ङ) यदि ये कम्पनियां उस राज्य में अब तक नहीं भेजी गई हैं तो इन्हें वहां कब तक भेज दिया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमन ।

(ग) से (ङ) नक्सलवादी समस्या से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकारों को केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की कुछ कम्पनियां उपलब्ध कराई गई हैं। उनकी तैनाती के संबंध में निर्णय लेना राज्य सरकारों का काम है।

अन्य राज्यों में तैनात की गई मध्य प्रदेश पुलिस की वाहिनियां

1026. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर अन्य राज्यों में तैनात की गई मध्य प्रदेश पुलिस की वाहिनियों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है और ये वहां कब से तैनात हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इन वाहिनियों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है; यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) किन-किन राज्यों में तैनात इन वाहिनियों के व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी है और प्रतिपूर्ति की धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस धनराशि की प्रतिपूर्ति कब तक कर दिए जाने की संभावना है ;

(ङ) क्या सरकार ने यह निदेश दिया है कि जिन राज्यों की वाहिनियां अन्य राज्यों में तैनात की जाएं उन्हें तिमाही 25 लाख रुपए की अग्रिम धनराशि अदा की जाए, यदि हां, तो क्या इस निदेश का पालन किया जा रहा है और यदि नहीं, तो यह निदेश किन-किन राज्यों में अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(च) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने किसी राज्य से अपनी वाहिनियां हटा लेने का अनुरोध किया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :-

चंडीगढ़	–	1 एम० पी० एस० ए० एफ० बटालियन जुलाई-अगस्त, 1990 से तैनात।
जम्मू और कश्मीर	–	एम०पी०एस०ए०एफ० की चार कम्पनियां अप्रैल, 1988 से तैनात हैं।

इसके अतिरिक्त, एम०पी०एस०ए० एफ० की 2 बटालियनें (इंडिया रिजर्व) 1971 में उनके गठित होने के बाद से राज्य के बाहर तैनात है। इस समय, इन बटालियनों की तैनाती निम्न प्रकार है :-

असम	–	4 कम्पनियां
त्रिपुरा	–	1 बटालियन
लक्षद्वीप	–	2 कम्पनियां

(ख) जी हां, श्रीमन् । मध्य प्रदेश सरकार को सूचना दी गई है कि वर्तमान